Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IX, Issue No. XVII, January-2015, ISSN 2230-7540

नीति आयोग: प्रासंगिकता पर उठते सवाल

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IX, Issue No. XVII, January-2015, ISSN 2230-7540

नीति आयोग: प्रासंगिकता पर उठते सवाल

Dr. Karambir*

Assistant Professor (Political Science), Government College, Dubaldhan, Jhajjar

सार *- भारत की विविधताओ से भरा देश हैउसकी अपनी कुछ जटिल समस्याएं हैं। रोजगार और आयय निवेश और प्रगतिय आर्थिक क्षेत्र का ऊलझावय अंतरराष्ट्रीय व्यापारय शिक्षा और स्वास्थ्यय जैसे क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ एक को सुलझाने पर दूसरी ओर स्थिति खराब हो सकती है। इन जटिलताओं को सुलझाने हेतु सशक्त नीति और सुदृढ़ रणनीति की जरूरत है।अब सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार के पास ऐसी नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाने की क्षमता है?*

जटिलता की इस चुनौती को समझते हुए प्रधानमंत्री ने 2015 में योजना आयोग का विघटन करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फार्मिंग इंडिया (नीति आयोग) का गठन किया था। समय के साथ, अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के कारण नीति आयोग को आज कठघरे में खड़ा कर दिया गया है। इसकी सार्थकता को जाँचे-परखे जाने की जरूरत है।

कुंजी शब्द – *भारत, रोजगार, निवेश, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फार्मिंग इंडिया (नीति आयोग), निजी क्षेत्र, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग चार्टर, सहभागिता।*

----------X----------

प्रस्तावना

स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की नीतिगत संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएँ बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाएँ काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएँ बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।

नीति आयोग के दो प्रमुख हब

टीम इंडिया हब – राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।

ज्ञान और नवोन्मेष (Knowledge & Innovation) हब – नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।

नीति आयोग ने तीन दस्तावेज़ जारी किये हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज़ और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज़ शामिल हैं।

नीति आयोग के उद्देश्य

- यह मानते हुए कि मज़बूत राज्य ही एक मज़बूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिये राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।
- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई हैं।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं।

www.ignited.in

- प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना।

- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना।

- राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हित धारकों तक उनको पहुँचाना।

प्रासंगिकता पर उठते सवाल

भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रशस्त करने की दिशा में नीति आयोग चार्टर की शुरूआत महत्वपूर्ण थी। एक जटिल, संघीय, सामाजिक-आर्थिक तंत्र में इस संस्था को उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के उद्देश्य से लाया गया था।वर्तमान संदर्भ में नीति आयोग की भूमिका को लेकर यह चिन्ता व्याप्त हो गई है कि आयोग, सरकार को दिशा-निर्देश देने वाली एक स्वतंत्र संस्था के रूप में अपनी अखंडता खो चुका है। यह सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है।

जटिलता की इस चुनौती को समझते हुए प्रधानमंत्री ने 2015 में योजना आयोग का विघटन करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फार्मिंग इंडिया (नीति आयोग) का गठन किया था। समय के साथ, अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के कारण नीति आयोग को आज कठघरे में खड़ा कर दिया गया है। इसकी सार्थकता को जाँचे-परखे जाने की जरूरत है।

मोदी से पूर्व, अटल बिहारी बाजपेयी और मनमोहन सिंह को भी इसी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और वैश्विक जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बाजपेयी जी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण प्रजातंत्र के लिए जिसमें राज्य, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्थाएं और विपक्षी दल अपनी भागीदारी निभाते हैंय नीतियों का कार्यान्वयन इतना आसान नहीं है। इसके लिए सुनियोजित रणनीति के साथ-साथ सहभागिता आधारित कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

मनमोहन सिंह ने योजना आयोग में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। कई हितधारकों से सलाह-मशविरा किया गया। वैश्विक कार्य-प्रणालियों को देखा गया था। योजना आयोग की एक ऐसी रूपरेखा खींची गई थी। जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की बजाय, उसके सिस्टम में सुधार की क्षमता विकसित की जा सके। बजट की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को दे दी गई।

उस दौरान नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में योजना आयोग की सीमाओं को समझा और उसके लिए प्रस्तावित सुधारों पर भी ध्यान दिया। यही कारण है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसे लागू करने में देर नहीं लगाई।लेकिन इस संस्था पर उठते सवाल सृजनात्मक सुधार की आवश्यकता पर बल प्रदान करते हैं।

भविष्य की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि नीति आयोग के पास केन्द्र व राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का स्वतंत्र अवलोकन करने की शक्ति है। कुछ का यह भी मानना है कि यूपी-2 सरकार के कार्यकाल में इसमें एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय हुआ करता था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। यहाँ वे भूल जाते हैं कि योजना आयोग के मूलभूत परिवर्तन के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। इसें परंपरागत रूप से चलने वाला नंबरों और बजट के बाद वाला मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इस 21वीं सदी के नीति आयोग के चार्टर में कार्य के संपन्न होने के साथ-साथ ही मूल्यांकन और सुधार किया जाता है। इसकी कार्यप्रणली में संगठनात्म्क सीख के ऐसे नए तरीकों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे इसके साथ जुड़े हितधारकों को साथ मिलकर नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने का लाभ मिल सके।

वास्तव में तो नीति आयोग चार्टर में पुराने कार्यक्रम को एक नया जामा पहना दिया है। इसमें ऐसे नए तरीके अपनाए जाने की आवश्यकता है, जो सहभागिता का मार्ग दिखाए। सरकार को चाहिए कि वह इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए इसकी क्षमता को इस प्रकार से बढ़ाए कि वह आगामी वर्षों का लक्ष्य घोषित करने वाली संस्था मात्र न रहकर अपनी भूमिका में प्रगति दिखाए।

संदर्भ सूची

1. द हिन्दू, अरुण मायरा का लेख (10 जून 2019)
2. http://www.niti.gov.in
3. http://niti.gov.in>e-book
4. http://hi.m.wikipedia.org
5. http://www.pmindia.gov.in

6. NITI AAYOG -ANNUAL REPORT-2019- 20(5 year of NITI AAYOG)

7. NITI AAYOG-THREE YEARS ACTION AGENDA 2017-18To2019-2

8. NITI Aayog Strategy for New India@75

Corresponding Author

Dr. Karambir*

Assistant Professor (Political Science), Government College, Dubaldhan, Jhajjar